

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित

2nd ग्रेड (द्वितीय श्रेणी अध्यापक)

/ सामाजिक विज्ञान (S.St.) /

लोक प्रशासन Public Administration

अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित

20 दिसम्बर 2024
को जारी
नवीनतम पाठ्यक्रम
के अनुसार



होशियार सिंह
(उप निरीक्षक राज. पुलिस)

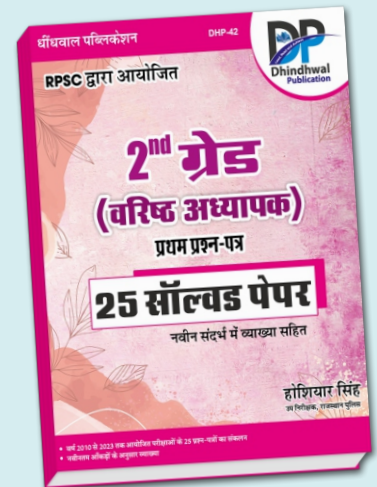
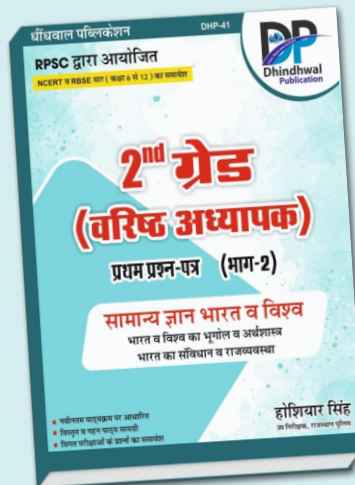
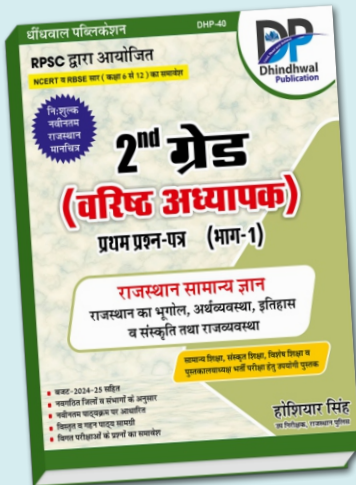
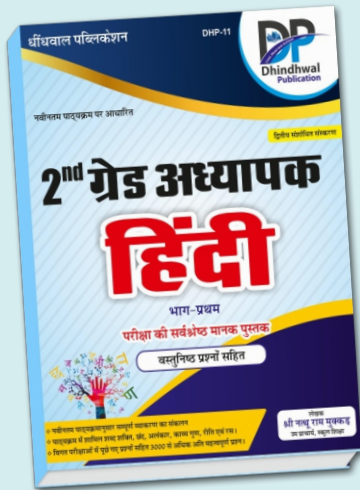
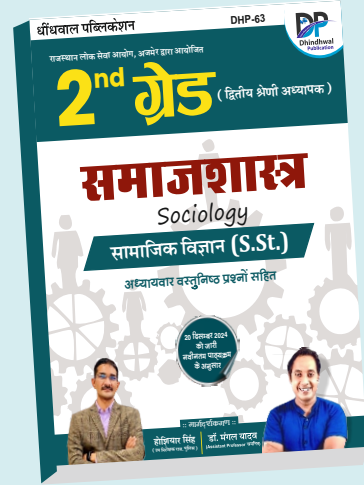
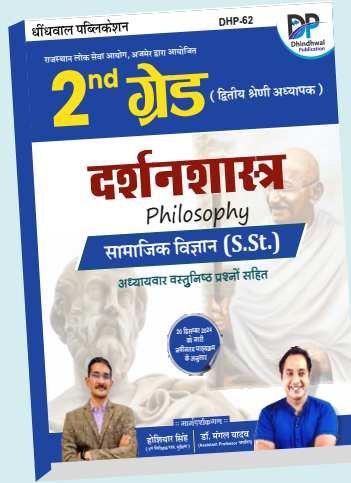
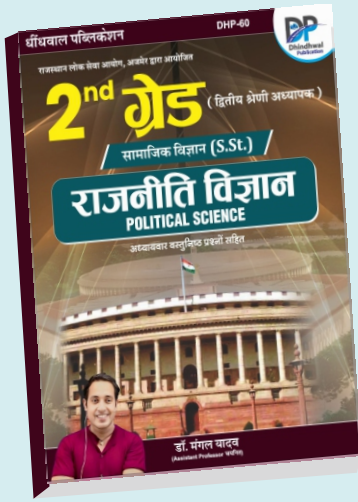
:: मार्गदर्शकगण ::

डॉ. मंगल यादव
(Assistant Professor चयनित)



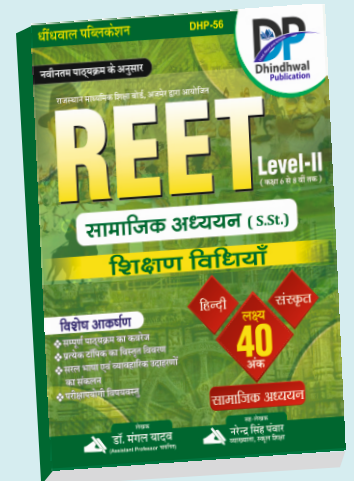
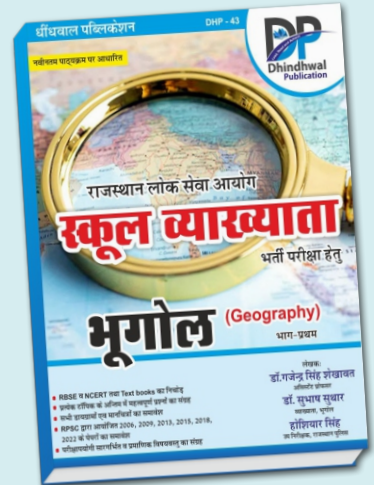
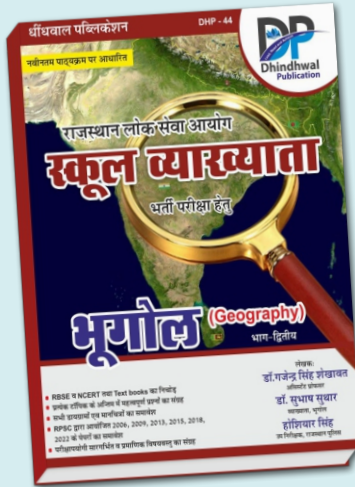
परीक्षा में सफलता हेतु इन पुस्तकों का अध्ययन करें

हमारे प्रकाशन की अन्य पुस्तकें



परीक्षा में सफलता हेतु इन पुस्तकों का अध्ययन करें

हमारे प्रकाशन की अन्य पुस्तकें





:: मार्गदर्शिका ::

होशियार सिंह

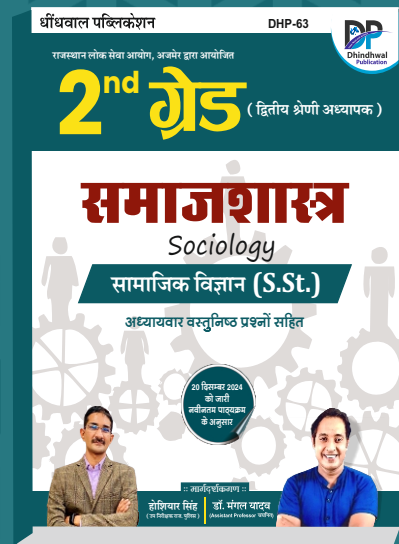
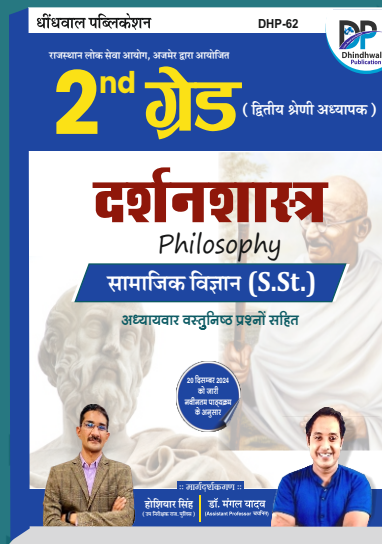
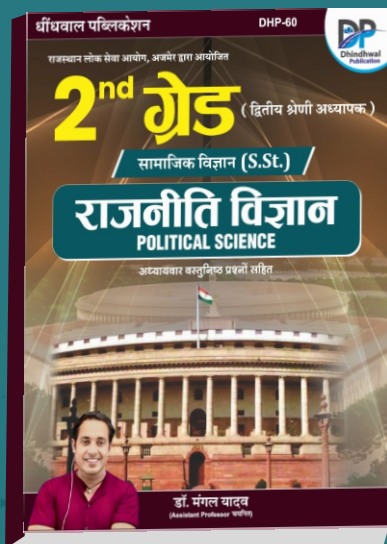
होशियार सिंह का जन्म ग्राम रतनपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरू (राजस्थान) में हुआ। आपने स्नातक करने के दौरान ही वर्ष 2003 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आरम्भ की, राजस्थान पुलिस (जिला बीकानेर वर्ष 2008) में कानिस्टेबल के पद पर चयन के साथ ही 2008 में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर चयन हुआ। आपने 5 वर्ष तक जिला राजसमंद में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएँ दी, तत्पश्चात् द्वितीय श्रेणी शिक्षक (हिन्दी) 2013 में चयन होने पर आपने राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कतरियासर (बीकानेर) में अपनी सेवाएँ दी, तत्पश्चात् राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक 2014 में चयन हुआ, वर्तमान में आप राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक हैं, आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में अध्यापन व मार्गदर्शन का गहन अनुभव है।

डॉ. मंगल यादव



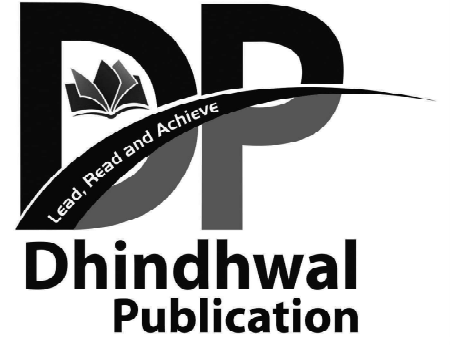
डॉ. मंगल यादव का जन्म जयपुर जिला, राजस्थान में हुआ। आपने स्नातक करने के दौरान ही प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया, इसी दौरान आप अनेक सरकारी सेवा में चयनित हुए। आपने राजस्थान की शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षण विधियों की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ' मंगल शिक्षण विधियाँ ' से लाखों विद्यार्थियों के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन व मार्गदर्शन का गहन अनुभव है।

हमारी अन्य पुस्तकें



धींधवाल पब्लिकेशन

प्रस्तुत करते हैं-



2nd ग्रेड (द्वितीय श्रेणी अध्यापक)

लोक प्रशासन
(Public Administration)

सामाजिक विज्ञान (S.St.)
(अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित)

- ✦ प्रामाणिक विषय-वस्तु का संकलन ।
- ✦ परीक्षाओं के नवीन पैटर्न के अनुसार गहन व व्यापक पाठ्यसामग्री का संकलन ।
- ✦ आरेख, मानचित्र, सारणियों सहित रोचक प्रस्तुतीकरण ।
- ✦ पुस्तक की भाषा सरल एवं प्रत्येक अवधारणा को उदाहरण सहित समझाया गया है ।

प्रकाशक:-

धींधवाल पब्लिकेशन

B-22, वैष्णो विहार, बीकानेर

मो. - 8306733800

लेखक:- डॉ. मंगल

(असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित)

प्रकाशक:-

धींधवाल पब्लिकेशन

B-22, वैष्णो विहार, बीकानेर

मो. - 8306733800

 - Dhindhwal Publication

 - धींधवाल पब्लिकेशन

 - Dhindhwal Classes

 - @Publication-DP

 - Dhindhwal Publication

बुक कोड- DHP- 61

© सर्वाधिकार- लेखक

फिक्स रेट- 100.00/-

मुद्रक-

पिंकसिटी ऑफसेट, जयपुर

इस पुस्तक के किसी भी अंश का लेखक तथा प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना मुद्रित करना, कराना तथा इस पुस्तक की व इस पुस्तक के किसी भाग की फोटोकॉपी, स्कैनिंग, इलेक्ट्रोस्टेट, मशीनी टंकण अथवा किसी भी तरीके से पुनः उपयोग करना, पी.डी.एफ बनाकर वाट्सअप या टेलीग्राम आदि पर प्रसारित करना पूर्णतः वर्जित है।

इस पुस्तक को तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है पुस्तक में दिये गये तथ्य व विवरण उचित व विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त किये गये हैं, फिर भी इसमें किसी त्रुटि, गलती, कमी अथवा लोप रह जाना संभव है। अतः ऐसी किसी भी त्रुटि, गलती, कमी अथवा लोप के कारण हुई क्षति अथवा क्लेश के लिए लेखक, प्रकाशक, सम्पादक, मुद्रक, विक्रेता व कर्मचारीगण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। आप उपर्युक्त सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से पुस्तक खरीद रहे हैं अतः दायित्व आपका स्वयं का होगा। सभी प्रकार के परिवादों का न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।

2nd ग्रेड (द्वितीय श्रेणी अध्यापक)

यूनिट	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
	RPSC 2nd ग्रेड परीक्षा (लोक प्रशासन) में पूछे गये प्रश्न	1-8
1.	लोक प्रशासन-अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्त्व और विकास	9-24
☞	प्रशासन का अर्थ, अभिप्राय, परिभाषाएँ एवं विशेषताएँ, लोक-प्रशासन व निजी प्रशासन में अन्तर, लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषाएँ, प्रकृति, क्षेत्र, प्रशासन और लोक प्रशासन में अन्तर, शासन व लोक प्रशासन में अन्तर, लोक प्रशासन की विशेषताएँ व भूमिका, लोक प्रशासन का अनुशासनात्मक रूप से मूल्यांकन, लोक प्रशासन का विकास (चरण), नवीन लोक प्रशासन (NPA), भारत में लोक प्रशासन का विकास, लोक प्रशासन व नवीन लोक प्रशासन में अन्तर, नव लोक प्रबंधन (NPM), विशेषताएँ	
☞	अभ्यास प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)	
2.	लोक प्रशासन-संगठन के सिद्धांत	25-74
☞	संगठन का अर्थ व परिभाषाएँ, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठनों में अन्तर, लोक प्रशासन के संगठन सिद्धांत (वैज्ञानिक प्रबन्ध, नौकरशाही सिद्धांत), औपचारिक संगठन के सिद्धांत (हेनरी फेयोल का सिद्धांत), लूथर का सिद्धांत, उर्निक का सिद्धांत, मून व रैले का सिद्धांत, एल्टन मेयो का सिद्धांत, व्यवहारवादी व्यवस्था सिद्धांत, संगठन का अन्य सिद्धांत (पदसोपान का सिद्धांत, नियंत्रण क्षेत्र का सिद्धांत, प्रत्यायोजन का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, संचार का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत)	
☞	अभ्यास प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)	
3.	प्रशासनिक व्यवहार-निर्णय लेना, नेतृत्व, संचार और प्रेरणा	75-88
☞	प्रशासनिक व्यवहार का अर्थ, निर्णय निर्माण का अर्थ व परिभाषाएँ तथा विशेषताएँ, निर्णय प्रक्रिया के सोपान, निर्णय प्रक्रिया के प्रकार, निर्णय निर्माण का मॉडल, निर्णय निर्माण से संबंधित विद्वानों के विचार, नेतृत्व का अर्थ, परिभाषाएँ, प्रकार एवं कार्य, गुण नेतृत्व शैलियाँ, नेतृत्व की विचारधारा, नेतृत्व के सिद्धांत	
☞	अभ्यास प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)	
4.	प्रथम व द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग	89-96
☞	प्रशासनिक सुधार का आशय, प्रशासनिक आयोग की स्थापना से पूर्व प्रयास, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग-1996, कार्य सिफारिशें, प्रतिवेदन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग-2005- कार्य, सिफारिशें, प्रतिवेदन। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग छठा वेतन आयोग 2006, साँतवां वेतन आयोग 2014	
☞	अभ्यास प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)	
5.	नागरिकों की शिकायतों का निवारण: लोकपाल, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार	97-106
☞	लोकपाल का अर्थ, लोकपाल विकास के चरण, क्षेत्राधिकार, चयन समिति, कार्य। लोकायुक्त का अर्थ, नियुक्ति, क्षेत्र व शक्तियाँ, लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम का विकास कार्य, धाराएँ, लाभ, उद्देश्य	
☞	अभ्यास प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)	

प्राक्कथन

प्रस्तुत पुस्तक मेरे पिताजी श्री बाबू शिव लाल यादव (Ex-Army Officer- वर्तमान पद प्रधानाध्यापक) के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह पुस्तक उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, जो राजस्थान में RPSC 2nd ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा के (सामाजिक विज्ञान S.St.) के लिए 'लोक प्रशासन' विषय की तैयारी कर रहे हैं।

इस पुस्तक में मैंने निम्न तथ्यों को सम्मिलित किया है-

1. पुस्तक की भाषा सरल एवं प्रत्येक अवधारणा को उदाहरण सहित समझाया गया है।
2. यह पुस्तक मानक पुस्तकों को आधार मानकर तथा RBSE/UGC/RPSC की विगत परीक्षाओं के प्रश्नों का विश्लेषण करके तैयार की गई है, ताकि विद्यार्थी सभी प्रश्नों को समझ सकें और सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे सकें।
3. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की पुस्तकों पर आधारित प्रामाणिक सामग्री का संकलन।
4. इस पुस्तक को इग्नो बोर्ड, विभिन्न ओपन विश्वविद्यालयों की पाठ्यपुस्तकों एवं विभिन्न संदर्भ पुस्तकों को आधार मानते हुए तैयार किया गया है।

इस पुस्तक के लेखन कार्य में मेरी बहन डॉ. पूजा यादव, भाई विजय यादव, दिनेश कुमार (I.A.S.), डॉ. ममता (Assistant Professor), डॉ. रेखा चौधरी (Assistant Professor), महेन्द्र फौजी माण्डेला (Indian Airforce) तथा धींधवाल पब्लिकेशन टीम का विशेष योगदान रहा है।

“दोस्तों, समय अपनी रफ्तार में है, अगर तुम रूके तो बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो, रूके तो हार जाओगे।”

लेखक:- डॉ. मंगल
(असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित)
मो. - 7976216970

RPSC 2nd ग्रेड परीक्षा (लोक प्रशासन) में पूछे गये प्रश्न

RPSC सेकंड ग्रेड (संस्कृत विभाग) भर्ती 2024

- कौन भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का सदस्य नहीं था?
 - (1) के. हनुमन्तैया
 - (2) वी. रामचन्द्रन
 - (3) जी.एस. पाठक
 - (4) हरिश चन्द्र माथूर
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न (2)
- निम्नलिखित में से कौनसा वैज्ञानिक प्रबन्ध का सिद्धांत नहीं है?
 - (1) अंगूठे के नियम के स्थान पर विज्ञान का उपयोग
 - (2) संघर्ष के स्थान पर मैत्री
 - (3) सहकारिता के स्थान पर व्यक्तिवाद
 - (4) सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न (3)
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के कौनसे प्रतिवेदन का नाम 'शासन में नैतिकता' है?
 - (1) चौथा प्रतिवेदन
 - (2) दसवां प्रतिवेदन
 - (3) दूसरा प्रतिवेदन
 - (4) सातवां प्रतिवेदन
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न (1)
- लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में निम्नांकित दृष्टिकोणों में से फिफनर एफ.एम. मार्क्स एवं एल.डी. व्हाइट द्वारा किस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है?
 - (1) प्रबन्धकीय दृष्टिकोण
 - (2) पोकोक दृष्टिकोण
 - (3) एकीकृत दृष्टिकोण
 - (4) आधुनिक दृष्टिकोण
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न (3)
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नांकित में से किसे भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया?
 - (1) ओ.पी. केजरीवाल
 - (2) ए.एन. तिवारी
 - (3) वजाहत हबीबुल्लाह
 - (4) एम.एम. अंसारी
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न (3)
- भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे?
 - (1) पन्द्रह
 - (2) अठारह
 - (3) दस
 - (4) बीस
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न (4)
- लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के संदर्भ में निम्न में से कौनसा सही नहीं है?
 - (1) पूर्व प्रधानमंत्री इसके क्षेत्राधिकार में है।
 - (2) यह 6 महीने में जाँच सम्पन्न करेगा।
 - (3) इसमें एक चेयरमैन तथा 8 सदस्य होंगे।
 - (4) इनमें से 5 न्यायिक सदस्य होंगे।
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न (4)
- निम्न में से कौनसा मानवीय संबंध उपागम का मुख्य प्रस्ताव नहीं है?
 - (1) अभिप्रेरण
 - (2) कर्मचारियों का निजी हित
 - (3) व्यक्तिगत अंतर
 - (4) कर्मचारियों का अनौपचारिक संगठन
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न (3)
- संगठन के 'मानव व्यवहार दृष्टिकोण' का अग्रदूत किसे माना जाता है?
 - (1) एल्टन मेयो
 - (2) हर्बर्ट साइमन
 - (3) मैरी पार्कर फोलेट
 - (4) चेस्टर बर्नार्ड
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न (4)
- निम्नलिखित में से कौन 'उदासीनता के क्षेत्र' से सम्बन्धित है?
 - (1) एम.पी. फोलेट
 - (2) एल्टन मेयो
 - (3) चेस्टर बर्नार्ड
 - (4) हर्बर्ट साइमन
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न (3)
- हेनरी फेयोल ने किसी औद्योगिक उपक्रम की समस्त क्रियाओं को कितने समूहों में बाँटा है?
 - (1) 9
 - (2) 8
 - (3) 6
 - (4) 5
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न (3)
- किस विचारक ने राजनीति-प्रशासन द्वन्द्व विचार का प्रारम्भ किया?
 - (1) डब्ल्यू.एफ. विलोबी
 - (2) वुडरो विल्सन
 - (3) मैरी पार्कर फोलेट
 - (4) हेनरी फेयोल
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न (2)
- तृतीय मिनोबुक कॉन्फ्रेंस सन् 2008 में आयोजित हुई जिसका थीम— 'भविष्य का लोक प्रशासन, भविष्य का लोक प्रबन्धन एवं भविष्य की लोक सेवाएँ' रखा गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी?
 - (1) विन्सेंट ऑस्ट्रोम
 - (2) विलियम ए. निस्कानेन
 - (3) रोजमेरी ओलेरी
 - (4) एल.डी. व्हाइट
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न (3)
- लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत, लोकपाल की नियुक्ति हेतु चयन समिति में कितने सदस्य होने चाहिये?
 - (1) एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य
 - (2) एक अध्यक्ष एवं पाँच सदस्य
 - (3) एक अध्यक्ष एवं तीन सदस्य
 - (4) एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य (5) अनुत्तरित प्रश्न (4)

16. संसद में लोकपाल विधेयक प्रथम बार कब प्रस्तुत हुआ था?
 (1) 1964 (2) 1966 (3) 1968 (4) 1971 (3)
17. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की किस धारा में सूचना के प्रकटन से छूट विहित है?
 (1) धारा 7(1) (2) धारा 7(2)
 (3) धारा 8(1) (4) धारा 8(2) (3)
18. राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जाँच नहीं कर सकता है?
 (1) भ्रष्टाचार (2) पद का दुरुपयोग
 (3) अकर्मण्यता
 (4) अनुशासनात्मक कार्यवाही (4)

- (1) आसूचना (2) प्रारूप
 (3) चयन (4) फीडबैक (प्रतिक्रिया) (4)
8. निम्न में से कौनसा एक मैरी पार्कर फोलेट द्वारा सुझाए गए नेतृत्व का प्रकार नहीं है?
 (1) पद से नेतृत्व (2) व्यक्तित्व से नेतृत्व
 (3) ज्ञान से नेतृत्व (4) कार्य से नेतृत्व (3)
9. निम्न में से कौनसा सम्प्रेषण प्रक्रिया का सही अनुक्रम है?
 (1) सम्प्रेषक, माध्यम, संदेश, संवाद प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया
 (2) संदेश, माध्यम, सम्प्रेषक, संवाद प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया
 (3) सम्प्रेषक, संदेश, माध्यम, संवाद, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया
 (4) सम्प्रेषक, संदेश, संवाद प्राप्तकर्ता, माध्यम, प्रतिक्रिया (3)

द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा-2022 (संस्कृत शिक्षा)

1. 'पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेन्स' पुस्तक के सम्पादक कौन थे?
 (1) ड्वाइट वाल्डो (2) फ्रैंक मैरेनी
 (3) रोबर्ट टी. गोलम्ब्यूस्की (4) विलियम एफ. विलोबी (1)
2. "लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है।" ये कथन किसका है?
 (1) वुडरो विल्सन (2) एल.डी. व्हाइट
 (3) डब्ल्यू.एफ. विलोबी
 (4) साइमन, स्मिथबर्ग एण्ड थॉमसन (2)
3. निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि 'पोस्ड कार्ब' शब्द के अन्तर्गत नहीं आती है?
 (1) नीति बनाना (2) समन्वय करना
 (3) निर्देश देना (4) रिपोर्ट बनाना (1)
4. निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक एफ.डब्ल्यू. टेलर से सम्बन्धित नहीं है?
 (1) शॉप मैनेजमेंट
 (2) प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट
 (3) जरनल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
 (4) द आर्ट ऑफ कटिंग मैटल्स (3)
5. निम्नांकित में से किसे व्यवहारवाद का जनक माना जाता है?
 (1) डेविड ईस्टन (2) चेस्टर बर्नार्ड
 (3) हर्बर्ट साइमन (4) रॉबर्ट प्रेस्थस (1)
6. निम्नलिखित चिंतकों में से किस एक ने संगठन में 'गैंग प्लंक' की अवधारणा का विकास किया?
 (1) लूथर गुलिक (2) लिन्दल उर्विक
 (3) हर्बर्ट साइमन (4) हैनरी फेयोल (4)
7. निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी एक हर्बर्ट साइमन द्वारा वर्णित निर्णय-निर्माण प्रक्रिया की गतिविधि नहीं है?

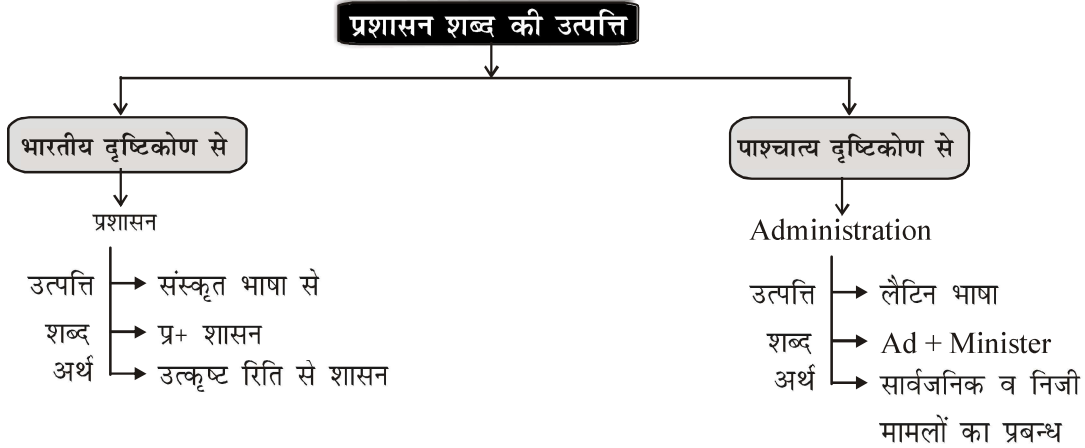
द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा-17 फरवरी, 2019

1. "लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है।" यह कथन है—
 (1) एल.डी. व्हाइट का (2) वुडरो विल्सन का
 (3) साइमन का (4) नीग्रो का (1)
2. लोक प्रशासन के एक पृथक विषय के रूप में विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है—
 (1) सिद्धांत निर्माण
 (2) राजनीति-प्रशासन द्विभागीकरण
 (3) अन्तर्विषयी अध्ययन
 (4) मनोवैज्ञानिक अध्ययनों की शुरुआत (2)
3. प्रशासन को 'दर्शन' मानने वाले प्रथम विचारक थे—
 (1) डिमॉक (2) वॉकर
 (3) स्मिथ (4) मेरियन लेविस (1)
4. 'निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सम्पादित समस्त प्रक्रियाओं का योग' का संबंध निम्न में से किससे है?
 (1) लोक प्रशासन अध्ययन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण से
 (2) लोक प्रशासन अध्ययन के शास्त्रीय दृष्टिकोण से
 (3) लोक प्रशासन अध्ययन के एकीकृत दृष्टिकोण से
 (4) लोक प्रशासन अध्ययन के व्यवहारवादी दृष्टिकोण से (3)
5. पोस्डकार्ब (POSD CORB) परिवर्णी शब्द में आर (R) से आशय है—
 (1) रेग्यूलर (नियमित) (2) रिपोर्टिंग (प्रतिवेदन)
 (3) रेवेन्यू (राजस्व) (4) रेजिस्टेन्स (प्रतिरोध) (2)
6. 'पद-सोपान पद्धति' का अन्य नाम है—
 (1) व्यवस्थित पद्धति (2) स्केलर पद्धति
 (3) आदेश की एकता (4) नियंत्रण सिद्धांत (2)
7. जेम्स डी मूने के अनुसार, संगठन का प्रथम सिद्धांत है—
 (1) भर्ती (2) समन्वय (3) बजट (4) प्रतिवेदन (2)

1

लोक प्रशासन- अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व और विकास

प्रशासन की उत्पत्ति



प्रशासन का अर्थ

- प्रशासन शब्द मुख्यतः अंग्रेजी शब्द Administration से बना है जो कि दो लैटिन उपसर्गों Ad + Ministrare से बना है। जिसका अर्थ है सेवा करना, प्रबन्ध करना या देखभाल करना। दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो प्रशासन शब्द, उत्कृष्टता, श्रेष्ठता, विशिष्टता, या पूर्णता से शासन करने की ओर इंगित करता है।

प्रशासन का अभिप्राय

- विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर किया गया सामूहिक प्रयास प्रशासन कहलाता है।

क्या आप जानते हैं?

सामान्यतः प्रयोग के आधार पर प्रशासन के चार अर्थ निकलते हैं।

1. सरकार या कार्यपालिका का प्रयाय माना जाता है।
2. सार्वजनिक विधि को लागू करने की क्रिया।
3. एक विषय के रूप में।
4. प्रबन्ध की कला के रूप में।

★ प्रशासन में निम्न तत्त्व पाये जाते हैं-

- दो या दो से अधिक व्यक्ति
- सामान्य लक्ष्य या उद्देश्य (Common Goal/Purpose)
- सामूहिक प्रयास (Collective Efforts)

क्या आप जानते हैं?

वैदिक काल में प्रशासन संस्कृत भाषा के 'प्रशास्ता' से बना है। यहाँ प्रशास्ता का अर्थ है- वैदिक यज्ञों का मुख्य पुजारी।

प्रशासन की परिभाषाएं

- ई.एन. ग्लैडेन के अनुसार - "प्रशासन एक लंबा और थोड़ा आडंबरपूर्ण

शब्द है, लेकिन इसका सीधा-सादा अर्थ है- मामलों का प्रबंध करना, लोगों की देखभाल करना या उनका ध्यान रखना। यह एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया सुनिश्चित कार्य है।"

- **फेलिक्स ए, निग्रो के अनुसार-** "किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों और सामग्रियों के संगठन और उपयोग को 'प्रशासन' कहते हैं।"
- **हरबर्ट ए, साइमन के अनुसार-** "अपने व्यापक अर्थ में 'प्रशासन' को समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग से काम करते समूहों की गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।"
- **एल.डी. व्हाइट के अनुसार,** "प्रशासन की कला किसी लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्य का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है।"
- **लूथर गुलिक के अनुसार,** "प्रशासन का सरोकर निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ कार्यों को करवाने से है।"

★ निष्कर्ष:

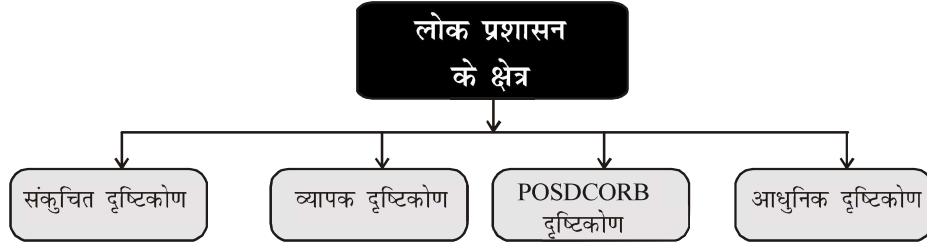
- उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है, कि प्रशासन के दो मूल घटक होते हैं-

 1. सामूहिक प्रयास
 2. समान लक्ष्य

प्रशासन की विशेषताएं

1. प्रशासन एक सामूहिक प्रयास है।
2. प्रशासन निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य।
3. प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है।
4. प्रशासन एक समन्वय की प्रक्रिया है।
5. प्रशासन बड़े संगठनों में पदसोपान की व्यवस्था है।
6. प्रशासन के दो रूप हैं-
 - (i) लोक प्रशासन
 - (ii) निजी प्रशासन

लोक प्रशासन के क्षेत्र



★ संकुचित दृष्टिकोण:

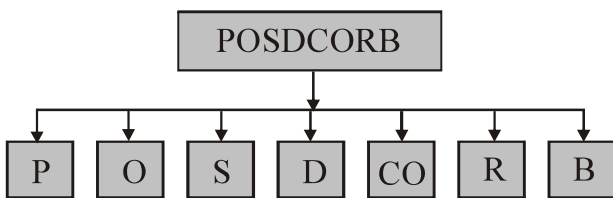
- व्यवहार में लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण को ही स्वीकार किया जाता है। इसके अनुसार लोक प्रशासन का सम्बन्ध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है। संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के अन्तर्गत कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन किया जाता है।
- **समर्थक:** एल.डी.व्हाइट, विलोबी

★ व्यापक दृष्टिकोण:

- व्यापक दृष्टिकोण का संबंध सरकार के तीनों अंगों से होता है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र को शामिल किया जाता है। जिसके द्वारा शासन के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है।
- **समर्थक:** लुथर गुलिक, साइमन, स्मिथबर्ग, थॉम्पसन

★ POSDCORB दृष्टिकोण:

- लोक प्रशासन के क्षेत्र या दायरे को लेकर लुथर गुलिक ने पोस्टकार्ब दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। गुलिक का मानना है कि लोक प्रशासन इन सात तत्त्वों (**P O S D CO R B**) से मिलकर बनता है। गुलिक द्वारा उक्त सात तत्त्वों की निम्नलिखित व्याख्या की गई है:-



- **P - Planning (योजना बनाना)**- निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक प्रभावी कार्यपद्धति या कार्य योजना तैयार करना। एक प्रभावी योजना सांगठनिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक अहम कदम होता है।
- **O - Organising (संगठित करना)** - प्राधिकार के औपचारिक ढाँचे का निर्माण एवं इसे परिभाषित करना। इसके माध्यम से संगठन में प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व का उचित निर्धारण किया जाता है।
- **S - Staffing (कार्मिकों की व्यवस्था)**- संगठन के लिए उपयुक्त कार्मिकों का चयन, प्रशिक्षण एवं नियुक्ति। यह संगठन को मानवीय संसाधन उपलब्ध कराने का माध्यम है।

- **D - Directing (निर्देशित करना)**- संगठन द्वारा लिये गये निर्णयों की सफल क्रियान्विति के लिए आदेश-निर्देश जारी करना ताकि सांगठनिक लक्ष्यों की सामयिक एवं कुशलतापूर्वक प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सके।
- **CO - Coordinating (तालमेल या समन्वय स्थापित करना)**- संगठन के विभिन्न अंगों एवं कार्यों के मध्य उचित तालमेल की स्थापना करना ताकि कार्य तय नीति एवं समय के अनुरूप सम्पादित हो सके। मूने-रैले द्वारा समन्वय को संगठन का प्रथम सिद्धांत कहकर सम्बोधित करना इसकी महत्ता को स्पष्ट करता है।
- **R - Reporting (सूचना प्रणाली)**- अधीनस्थों की उनको सौंपे गये कार्य के संदर्भ में उच्चस्थों के प्रति जबाबदेही तय करना। इसके माध्यम से संगठन में नियंत्रण प्रणाली की स्थापना हो पाती है।
- **B - Budgeting (बजट निर्माण)**- संगठन की सम्पूर्ण गतिविधियों को सम्पन्न करने के लिए आर्थिक संसाधनों का उचित एवं व्यवस्थित उपयोग। यह सांगठनिक संसाधनों के सन्दर्भ में कुशलता एवं मितव्ययता की स्थापना करता है।

☞ क्या आप जानते हैं?

- लुथर गुलिक ने POSDCORB में 1971 में 'E' (Evaluation) अर्थात् मूल्यांकन जोड़ा। इस प्रकार पोस्टकार्ब शब्द की संरचना है- **POSDECORB**।

★ आधुनिक दृष्टिकोण:

- लोक प्रशासन के इस क्षेत्र को आधुनिक- आदर्शवादी या लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि वर्तमान समय में राज्य का स्वरूप कल्याणकारी-राज्य का हो गया है। अतः लोक प्रशासन का क्षेत्र भी उसी के अनुरूप जनता के हित व कल्याण का होना चाहिए।
- एल.डी. व्हाइट: 'लोक प्रशासन को अच्छी जिंदगी के लक्ष्य का साधन मानते हैं।'
- वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्यों के बढ़ते कार्यक्षेत्र के साथ ही लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हो गया है। इस कारण लोक प्रशासन के अन्तर्गत केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय सभी स्तरों की सरकारों का अध्ययन किया जा रहा है।

4. मिनीबुकस सम्मेलन:

I- सम्मेलन (1968)	II - सम्मेलन (1998)	III- सम्मेलन (2008)
केवल युवा शामिल अमेरिकी सामाजिक आर्थिक उथल पुथल के दौर में प्रशासन के 4 लक्ष्य तय - 1. मूल्य 2. समता 3. परिवर्तन 4. प्रासंगिकता यह सम्मेलन लोक प्रशासन का आलोचक था। अध्यक्ष- ड्वाइट वाल्डो	युवा + वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति वैश्विक आर्थिक सुधारों के समय प्रशासन में 3E शामिल - 1. Economy 2. Efficiency 3. Effectiveness सरकार की सीमित भूमिका पर बल 4 D का सिद्धांत प्रतिपादित अध्यक्ष - जॉर्ज फ्रेडरिक्स	13 देशों के 200 प्रतिनिधि शामिल अमेरिका में आर्थिक मंदी के समय & E- Govt. का दौर प्रशासन TAR के समावेश पर बल दिया। पारदर्शिता (T) उत्तरदायित्व (R) जबाबदेहिता जनकल्याणकारी कार्यों पर जोर अध्यक्ष - प्रो. रोजमैरी ओ 'लीरी'

क्या आप जानते हैं ?

मिनी बुक्स सम्मेलन 2028 में आयोजित होगा।

- 1971 में मेरीनो द्वारा **मिनीबुक** सम्मेलन के विचारों को संकलित करके "टूवाइस ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन: मिनीबुक पर्सपेक्टिव" नामक पुस्तक प्रस्तुत की गई।

➤ नवीन लोक प्रशासन के 3 प्रतिलक्ष्य (Anti Goals) थे:

- यह लोक प्रशासन की ऐसी किसी भी परिभाषा को नकारता है जिसमें मूल्यों को उचित स्थान न दिया गया हो अर्थात् यह लोक प्रशासन के मूल्य-मुक्त (Value Free) स्वरूप को नकारता है।
- इसके द्वारा मानवीय व्यवहार में तार्किकता का विरोध करता है। इसके अनुसार मानवीय व्यवहार के संदर्भ में पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है।
- यह राजनीति-प्रशासन द्विभाजन का विरोधी है। इसके अनुसार लोक सेवक न केवल नीति-निर्माण में सक्रिय रूप में भाग लेते हैं बल्कि इन्हीं के द्वारा इन नीतियों को क्रियान्वित भी किया जाता है।
- लोक प्रशासन के परम्परागत सिद्धांत की मुख्य चिंता थी 'कार्यकुशलता एवं मितव्ययता' जो कि बदली हुई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में अपर्याप्त प्रतीत होने लगी। समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं का प्रादुर्भाव हो रहा था जिसके चलते लोक प्रशासन को नए सिद्धांत एवं विचारों की आवश्यकता थी।

NPA के लक्ष्य/नारे

- इस सम्मेलन का सार निम्न चार बिन्दुओं में प्रस्तुत किया जा सकता है:-

NPA के चार लक्ष्य

- प्रासंगिकता
- मूल्य
- समता
- परिवर्तन

- **प्रासंगिकता**- लोक प्रशासन की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक प्रासंगिकता सहित व्यवहारिकता पर बल दिया गया।
- **मूल्य**- लोक प्रशासन में मूल्यों पर बल दिया। क्योंकि मूल्य युक्त प्रशासन का शोषित, दमित, सुविद्याविहीन वर्ग की ओर झुकाव रहता है।
- **समता** - NPA सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला प्रशासन है।
- **परिवर्तन** - NPA सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन का समर्थक है।
- नवीन लोक प्रशासन द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 4-D वकालत की गई जो इस प्रकार है-

1. Decentralisation - विकेन्द्रीकरण
2. Debureaucratisation - गैर-नौकरशाहीकरण
3. Delegation - प्रत्यायोजन
4. Democratisation - लोकतंत्रीकरण

★ **NPA की विशेषताएं**

- NPA** अपने राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, पदसोपान, केन्द्रीकरण जैसे सिद्धांतों का विरोध किया।
- NPA** ने पद सोपान में लचीलापन, विकेन्द्रीकरण, विनौकरशाहीकरण एवं प्रशासन में जन सहभागिकता का समर्थन किया।
- NPA** ने चार लक्ष्यों का निर्धारण किया। (प्रासंगिकता, मूल्य, समता, परिवर्तन)
- NPA** ने ग्राहकोन्मूकता पर बल दिया।
- NPA** ने लोकतांत्रिकरण का समर्थन किया।

★ **NPA की आलोचना:**

- विकासशील देशों के लिए अधिक प्रासंगिक नहीं है।
- एक तरफ **NPA** प्रशासनिक तंत्र पर अपनी निर्भरता दर्शाता है, दूसरी तरफ यह अवधारणा विनौकरशाही का समर्थन करती है जो एक दूसरे के विरोधी है।
- NPA** मूल्यों पर अधिक बल देता है।

नव लोक प्रबन्धन की विशेषताएँ

नव लोक प्रबन्धन की विशेषताएँ

- उद्यमी सरकार
- उप्रेरक सरकार
- परिणाम आधारित सरकार
- उपभोक्ता संचालित सरकार
- पूर्वानुमान आधारित सरकार
- बाजार आधारित सरकार
- उद्देश्य आधारित सरकार
- साम्प्रदायिकता आधारित सरकार
- प्रतिस्पर्धात्मक आधारित सरकार
- विवेन्द्रीकृत सरकार

✦ एन्टी-गोल्स के अनुसार नव लोक प्रबन्धन

- यह राजनीति-प्रशासन द्विभाजन का विरोध करता है।
- यह संगठन के पदसोपानिक ढाँचे को अस्वीकार करता है
- अत्यधिक केन्द्रीकरण का विरोधी है।
- पूर्ण तार्किकता की अवधारणा को स्वीकार करता है।
- प्रशासन की निर्व्यक्तिक प्रकृति को अस्वीकार करता है।
- प्रशासन में अत्यधिक दृढ़ता या कठोरता का अस्वीकार करता है।

✦ नव लोक प्रबन्धन के प्रभाव

- सरकार द्वारा स्वायत्तशाली संस्थाओं या संगठनों की स्थापना।
- सरकार के आकार को छोटा करना (91वाँ संविधान संशोधन-मंत्रिपरिषद का आकार विधायिका की संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।)
- लोक उपक्रमों का निजीकरण।
- खुला एवं पारदर्शी प्रशासन।
- प्रशासन में जनभागीदारी (सामाजिक अंकेक्षण)
- सिटीजन चार्टर।

अभ्यास प्रश्न

1. लूथर गूलिक द्वारा प्रतिपादित पोस्टकार्ब निम्नलिखित कार्य की ओर इंगित करता है-
 - (1) सूत्र एजेंसी
 - (2) नियंत्रक एजेंसी
 - (3) कार्यरत एजेंसी
 - (4) मंत्रण एजेंसी
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न (1)
2. नवीन लोक प्रशासन विचारधारा किस तत्व पर बल देती है-
 - (1) लाभ कमाना
 - (2) कार्यकुशलता
 - (3) सामाजिक समता
 - (4) कानून एवं व्यवस्था
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न (3)
3. व्यवहारिक दृष्टिकोण निम्न में से किस पर मुख्य रूप से बल देता है?
 - (1) प्रशासकीय ढाँचा
 - (2) आर्थिक प्रोत्साहन
 - (3) मानवीय तत्व
 - (4) तकनीकी दक्षता
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न (3)
4. एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लेटिन भाषा के दो शब्दों एड तथा मिनिस्ट्रियर से मिल कर बना है जिसका अर्थ है-
 - (1) मंत्रालय के संसाधनों में वृद्धि करना
 - (2) सरकार को सलाह देना
 - (3) कार्यों की व्यवस्था में व्यक्तियों की देखभाल करना
 - (4) सरकार का संचालन
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न (3)
5. 1812 में फ्रेन्च भाषा में लोक प्रशासन पर लिखे गये प्रथम प्रथक शोध "प्रिन्सिपलेस दे एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक" के लेखक थे?
 - (1) हरबर्ट साइमन
 - (2) चार्ल्स ज्यां बूनिन
 - (3) एल.डी.व्हाइट
 - (4) विल्सन
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न (2)
6. विल्सन के किस लेख ने उन्हें लोक प्रशासन के जनक का सम्मान दिलाया?
 - (1) इन्ट्रोडक्शन टू दि स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने
 - (2) दि स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने
 - (3) पेपर्स ऑन दि साइन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने
 - (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न (2)
7. लोक प्रशासन को एकेडमिक मान्यता दिलाने वाली पुस्तक का नाम बताइये?
 - (1) पॉलिटिक्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन
 - (2) एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर
 - (3) प्रिन्सिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
 - (4) इन्ट्रोडक्शन टू दि स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
 - (5) अनुत्तरित प्रश्न (4)

लोक प्रशासन- संगठन के सिद्धांत

+ संगठन का अर्थ:

- मानव अपने हितों की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्तर पर प्रयास करता है। जब वह सामूहिक स्तर पर कोई भी प्रयास करता है तब उसके प्रयासों और प्रक्रियाओं को 'संगठन' के नाम से संबोधित किया जाता है। संगठनात्मक प्रयास सामाजिक तथा प्रशासनिक दोनों ही स्तरों पर किए जाते हैं। किन्तु संगठन, चाहे सामाजिक हो या प्रशासनिक, किसी विशेष उद्देश्य या प्रयोजन की प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता है।
- **संगठन क्या है?** - 'संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश' में 'टु ऑर्गेनाइज' (To Organise) शब्द का अर्थ 'तैयार करना अथवा चालू अवस्था में रखना' है। सामान्यतः 'संगठन' को तीन विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है:-
 - (1) प्रशासकीय संरचना का नमूना तैयार करना;
 - (2) संरचना का नमूना तैयार करना तथा उसका निर्माण करना
 - (3) स्वयं संरचना।
- **प्रो. अवस्थी एवं प्रो. माहेश्वरी** ने 'संगठन' शब्द का इन तीनों विभिन्न रूपों में प्रयोग होने पर निम्नलिखित तीन उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट किया है-
 - (1) राम में संगठन करने की योग्यता है।
 - (2) राम अपने यूनिट के निर्माण में व्यस्त है।
 - (3) भारत सरकार का ढाँचा।

क्या आप जानते हैं?

- **एल० उरविक** ने लोक प्रशासन में संगठन शब्द का संकीर्ण अर्थ लेते हुए इसे केवल प्रशासनिक संरचना के रूपांकन तक ही सीमित रखा है। उरविक मोटर कार की उपमा देते हुए कहते हैं कि कार का रूपांकन, उसका निर्माण तथा स्वयं कार, ये तीन भिन्न अवस्थाएँ हैं। वे मानते हैं कि जिस प्रकार रूपांकन का अर्थ निर्माण नहीं है, और निर्माण या रूपांकन में से किसी का भी अर्थ कार नहीं है। उसी प्रकार संगठन शब्द का प्रयोग संगठन के निर्माण करने अथवा अन्ततः निर्मित स्वयं प्रशासनिक ढाँचे के लिए किया जाना उचित नहीं होगा अतः संगठन शब्द का अर्थ केवल (प्रशासनिक) मशीन का रूपांकन ही लगाया जाना चाहिए। वे संगठन की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि 'यह निश्चित करना कि अमुक ध्येय या उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन-कौन सी क्रियाएँ अनिवार्य हैं और उनको समूहों में विभक्त करना, ताकि वे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को सौंपी जा सकें, संगठन कहलाता है।'

+ संगठन की परिभाषाएँ

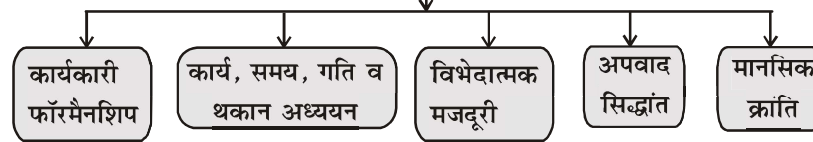
1. **एल.डी. हाईट के अनुसार**, "संगठन कर्मचारियों की वह व्यवस्था है जो कार्यों तथा दायित्वों के विभाजन के माध्यम से स्वीक व उद्देश्य की प्राप्ति में सुविधा प्रदान करती है।"
2. **मूने एवं रेलै के अनुसार**, "किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव-सहयोग का नाम ही संगठन है।"
3. **हरबर्ट साइमन के अनुसार**, 'परस्पर व्यवहार करने वाले लोगों के वर्ग का नाम संगठन है।'
4. **ई. एन. ग्लेडन के अनुसार**, 'संगठन, किसी उद्यम में लगे हुए मनुष्यों के बीच सम्बन्धों का ऐसा स्वरूप है जिससे कि उद्यम के कार्यों की पूर्ति हो सके।'
5. **मैक्फॉरलैण्ड के अनुसार**, 'व्यक्तियों के निश्चित समूह द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जानेवाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं।'
6. **एल. उरविक के अनुसार**, 'संगठन का अर्थ है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण और उन्हें ऐसे वर्ग में क्रमबद्ध करना जो विभिन्न व्यक्तियों को सौंपी जा सकें।'
7. **लूथर गूलिक के अनुसार**, "संगठन सत्ता की वह औपचारिक संरचना है जिसके माध्यम से परिभाषित उद्देश्य के लिए कार्य सम्बन्धी प्रयोगों को व्यवस्थित, परिभाषित तथा समायोजित किया जाता है।"
8. **फिफनर के अनुसार**, "संगठन में व्यक्ति का व्यक्ति से तथा समूह का समूह से इस प्रकार सम्बन्ध जोड़ा जाता है कि ठीक प्रकार से श्रम विभाजन हो जाए।"

+ निष्कर्ष:

- उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि संगठन एक मानवीय समूह है। किन्तु किसी भी मानवीय समूह को हम संगठन नहीं कह सकते। केवल उसी मानवीय समूह को संगठन कहा जा सकता है जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इकट्ठे हुए हैं। दूसरे, संगठन में मानवीय तत्व महत्वपूर्ण हैं, किन्तु इसके साथ ही भौतिक संसाधनों का भी संगठन में काफी महत्व है तथा जब तक इन्हें एकीकृत नहीं किया जाएगा, संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल नहीं हो सकता।

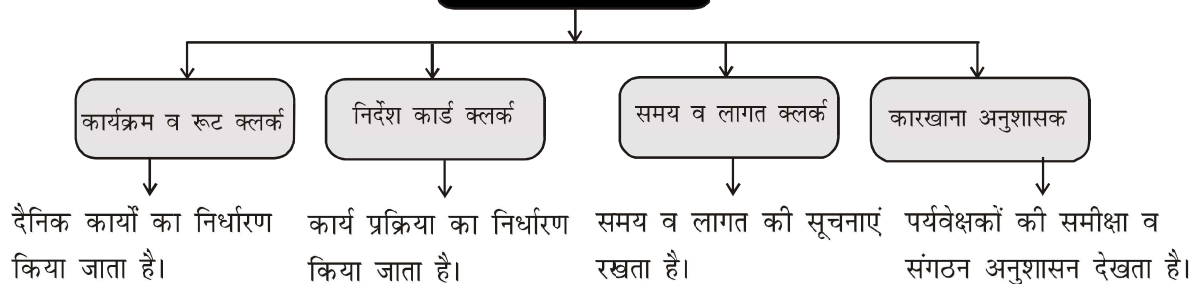
वैज्ञानिक प्रबंध के तरीके व तकनीकी

वैज्ञानिक प्रबंध के तरीके व तकनीकी

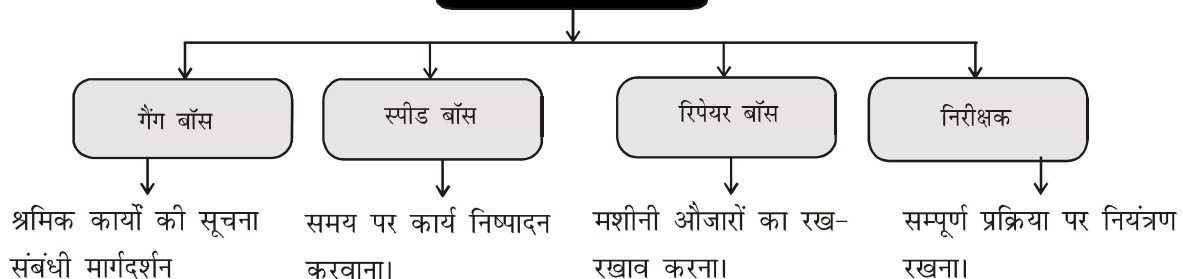


1. **कार्यात्मक फोरमैनिशप** : फेडरिक टेलर ने प्रबंध के लिए पहला तरीका कार्यात्मक फॉरमैनिशप बताया जो कार्य को विशिष्टीकरण के आधार पर वर्गीकृत करके प्रबंध को संचालित करने के लिए निम्न स्तर बताये जिनको चित्रों के माध्यम से समझते हैं-

नियोजन का स्तर



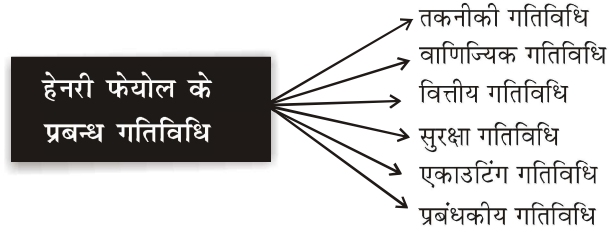
वर्कशॉप के स्तर



2. **कार्य, समय, गति व थकान अध्ययन** -कार्य के निष्पादन में लगने वाले उचित समय का निर्धारण ही समय अध्ययन है। इसके अन्तर्गत एक स्वस्थ श्रमिक द्वारा अपने शरीर को हानि पहुँचाये बिना किसी कार्य को करने में लिये जाने वाले न्यूनतम समय का निर्धारण किया जाता है जो कि उस कार्य के लिए मानक समय होता है। (वैज्ञानिक तरीके से निर्धारण)
- गति अध्ययन (Motion Study) -अनावश्यक शारीरिक गतियों को समाप्त कर कार्य करने की **श्रेष्ठ रीति (One Best way)** का विकास ताकि कार्य न्यूनतम शारीरिक ऊर्जा एवं समय में सम्पादित हो सके। (किसी कार्य विशेष में समाहित सभी गतियों का **अवलोकन**:- गतियों के सर्वश्रेष्ठ समुच्चय का निर्धारण)।
 - टेलर ने कार्य के दौरान होने वाली कार्मिक की थकान को दूर करने के लिए समय-समय पर विश्राम की वकालत की जिससे कार्मिक विश्राम के बाद पुनः पूर्ण ऊर्जा के साथ कार्य कर सकें।
3. **विभेदात्मक मजदूरी** - इस सिद्धांत के अंतर्गत कर्मचारियों के कार्यों का विभेदीकरण किया जाता है जिसमें अभिप्रेरणा के लिए ज्यादा मजदूरी कम काम कम मजदूरी। गाजर व छड़ी का सिद्धांत इसी सिद्धांत पर आधारित है इसलिए इसे 'अन्तर पीस रेट योजना' भी कहा जाता है।
- **अन्तरीय पीस रेट सिस्टम**
1. **मानक से कम उत्पादन पर** -निम्न पीस रेट।
 2. **मानक उत्पादन पर** - निर्धारित पीस रेट।
 3. **मानक से ऊपर उत्पादन पर** - ऊर्चे पीस रेट एवं बोनस।

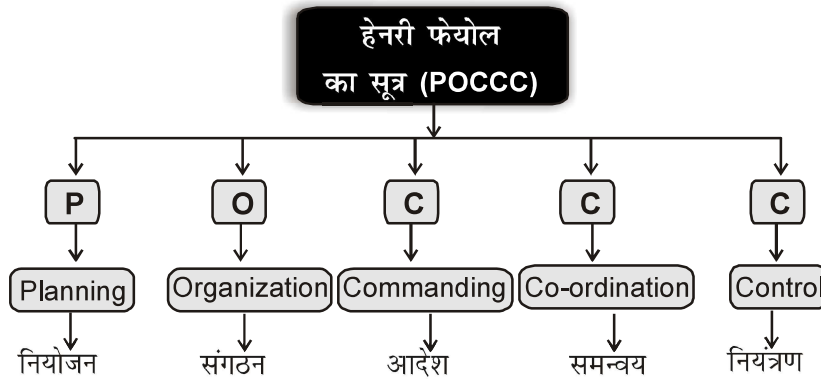
★ हेनरी फेयोल की औद्योगिक गतिविधि:

- हेनरी फेयोल द्वारा किसी औद्योगिक उपक्रम की निम्न गतिविधियों का उल्लेख किया:



- तकनीकी गतिविधियाँ - उत्पादन से जुड़ी गतिविधियाँ।
- वाणिज्यिक गतिविधियाँ - क्रय, विक्रय एवं प्रचार-प्रसार से जुड़ी गतिविधियाँ।
- वित्तीय गतिविधियाँ - पूँजी अर्थात् आर्थिक संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग।
- सुरक्षा संबंधी गतिविधियाँ - जान-माल की रक्षा से जुड़ी गतिविधियाँ।
- एकाउंटिंग गतिविधियाँ - स्टॉक, बैलेंस सीट, लाग, सांख्यिकी इत्यादि।
- प्रबंधकीय गतिविधियाँ - नियोजन, संगठन, निर्देश, समन्वय व नियंत्रण (POCCC- Planning, Organising, Commanding, Co-ordinating, Control)

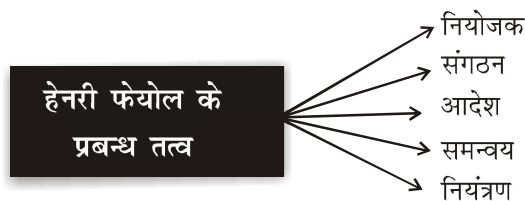
हेनरी फेयोल का प्रबंधन सूत्र



क्या आप जानते हैं?

- हेनरी फेयोल के अनुसार किसी भी प्रबन्धक के छह विशेष गुण या कुशलताएँ होनी चाहिए जो इस प्रकार हैं-
 - (1) शारीरिक
 - (2) मानसिक
 - (3) नैतिक
 - (4) सामान्य शिक्षा
 - (5) विशेष ज्ञान
 - (6) अनुभव

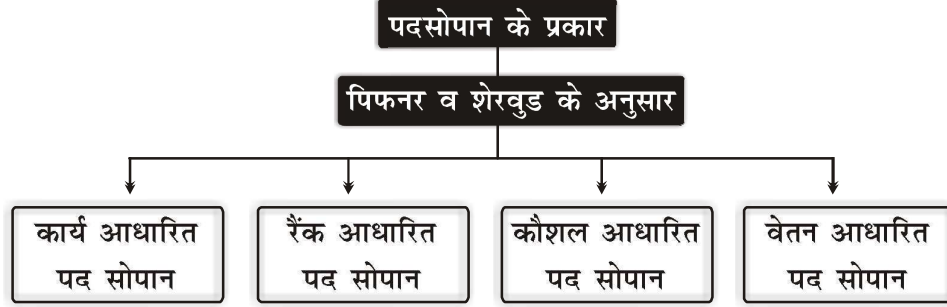
हेनरी फेयोल के प्रबंधन के तत्व



- नियोजन (Planning)**- कार्य करने से पूर्व उसकी तैयारी करना नियोजन कहलाता है। नियोजन में पूर्वानुमान एवं निर्णय को शामिल किया जाता है। इसके अन्तर्गत भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है और कार्य की योजना तैयार की जाती है। कार्य की योजना उद्यम के साधनों, कार्य की प्रकृति एवं व्यवसाय की भावी प्रवृत्तियों पर निर्भर करती है। एक अच्छी योजना के अन्तर्गत एकता, निरन्तरता, लोचशीलता, और निश्चितता के गुण होने चाहिए।
- संगठन (Organisation)** - फेयोल के अनुसार संगठन का तात्पर्य किसी व्यवसाय को संचालन करने के लिए समस्त उपयोगी एवं आवश्यक वस्तुओं जैसे कच्चा माल, औजार, पूँजी एवं कर्मचारी आदि उपलब्ध कराना है। फेयोल ने संगठन को दो भागों में बाँटा है। (अ) भौतिक संगठन (ब) मानवीय संगठन। फेयोल ने मानवीय संगठन को ही प्रबन्ध का तत्व माना है।

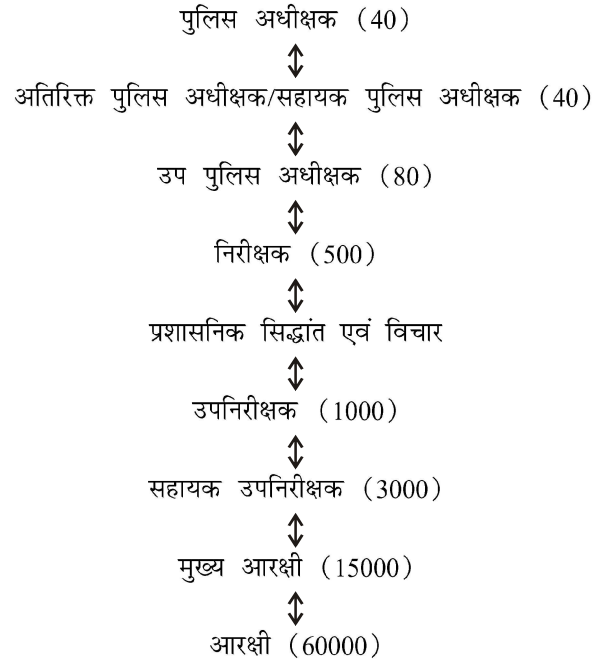
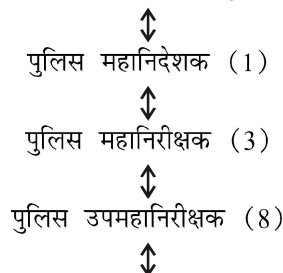
(vi) इसमें अधिकार तथा उत्तरदायित्व के मध्य समुचित तालमेल रखा जाता है, क्योंकि बिना उत्तरदायित्वों के अधिकार, खतरनाक हो जाते हैं तथा बिना अधिकार के उत्तरदायित्व, अर्थहीन हो जाते हैं।

✦ पदसोपान के प्रकार



1. **कार्य आधारित पदसोपान:** इस प्रणाली में प्रत्येक कार्मिक का स्थान उसके द्वारा किए जा रहे या उसे प्रदत्त किए गए कार्यों के आधार पर निश्चित होता है। कार्मिक जिस प्रकार का कार्य करता है उसी के अनुरूप उसे अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान किए जाते हैं। स्वाभाविक रूप से अधिक अधिकारों से युक्त व्यक्ति, उच्च पद पर तथा तुलनात्मक रूप से कम अधिकार प्राप्त व्यक्ति, पदसोपान में निम्न पद पर होता है।
2. **रैंक (प्रस्थिति) आधारित पदसोपान:** इस प्रणाली में कर्मिकों की स्थिति उनके कार्य तथा उत्तरदायित्वों के आधार पर न होकर, पद के आधार पर होती है। सेना में प्रचलित यह प्रणाली पद प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण मानती है। सेना का एक कर्नल चाहे, मोर्चे पर आदेश दे या सेना मुख्यालय में फाइलें निपटाये, वह कर्नल ही रहेगा।
3. **कौशल आधारित पदसोपान:** पदसोपान की इस पद्धति में कार्मिक की योग्यता तथा दक्षता पर बल दिया जाता है। किसी कारखाने में कार्यरत इंजीनियर या अस्पताल में डाक्टर उच्च कौशल युक्त होते हैं जिनकी सहायतार्थ अनेक सहायक विशेषज्ञ एवं तकनीकी कार्मिक कार्य करते हैं। उच्च विशेषज्ञता प्राप्त कार्मिक, उच्च पद पर रहता है।
4. **वेतन आधारित पदसोपान:** जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है अधिकतम वेतन पाने वाला अधिकारी संगठन के शीर्ष पर तथा कम वेतन पाने वाले कार्मिक क्रमशः नीचे के पदों पर होते हैं। वस्तुतः प्रशासनिक संगठनों में पदसोपान किसी एक प्रणाली पर आधारित न होकर सभी प्रणालियों या कुछ प्रणालियों के समन्वय पर आधारित होता है।

पदसोपान : एक उदाहरण (पुलिस प्रशासन)



✦ पदसोपान के लाभ:

- (i) प्रत्येक बड़े संगठन में आदेश की एकता रहनी आवश्यक है जिसे केवल पदसोपान व्यवस्था के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।
- (ii) पदसोपान को संगठनात्मक समन्वय, एकजुटता तथा अनुशासन का आधार माना जाता है क्योंकि इसमें संगठन की विभिन्न इकाइयों परस्पर जुड़कर एक संयुक्त ढाँचे का निर्माण करती हैं।
- (iii) यह व्यवस्था, संगठन में नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे के सम्पर्क या संचार माध्यम स्पष्ट करती है। इससे प्रत्येक कार्मिक को यह स्पष्ट रहता है कि उसका सम्बन्ध किससे है।
- (iv) इसमें, संगठन के प्रत्येक स्तर और पद पर उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना सुविधाजनक हो जाता है। प्रत्येक कार्मिक को संगठन में अपनी स्थिति तथा उत्तरदायित्वों का ज्ञान हो जाता है तथा उसे यह भी पता रहता है कि वह किसके प्रति उत्तरदायी है।

3

प्रशासनिक व्यवहार-निर्णय लेना, नेतृत्व, संचार और प्रेरणा

★ प्रशासनिक व्यवहार का अर्थ:

- मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का ही एक विशिष्ट प्रकार प्रशासनिक व्यवहार है। प्रशासनिक व्यवहार उन व्यक्तियों और समूह के व्यवहार को कहते हैं, जो कि प्रशासनिक संगठनों में औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से कार्य करते हैं।
- यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सांगठनिक लक्ष्यों एवं कार्मिकों की संतुष्टि की प्राप्ति हेतु संगठन से जुड़े कार्मिकों के व्यवहार में इस

प्रकार परिवर्तन लाया जाता है कि वे न केवल संगठन को अपने अधिकतम प्रयास देते हैं बल्कि इससे सांगठनिक लक्ष्यों की सामयिक प्राप्ति भी सुनिश्चित होती है।

☞ क्या आप जानते हैं?

- प्रशासनिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया है जिनमें हबर्ट साइमन, राबर्ट मरट, चेस्टर बर्नाड, पीटर ब्लाउ, कर्ट लेविन, रेन्सिस लिकर्ट इत्यादि प्रमुख हैं।

निर्णय निर्माण (Decision Making)

- मनुष्य का व्यवहार वास्तव में निरन्तर लिए जाने वाले निर्णयों की ही एक श्रृंखला होता है। जहाँ व्यवहार एक बृहद इकाई (Macro Unit) है वहीं निर्णय उसकी एक सूक्ष्म इकाई (Micro Unit) है। लगातार लिए गए निर्णयों की श्रृंखला से ही व्यवहार बनता है। साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण संगठन में सभी स्तरों पर व्याप्त होता है। अतः उन्होंने संगठन को निर्णयकर्ताओं की एक श्रृंखला के रूप में देखा है। उन्होने प्रशासन और निर्णय निरूपण के मध्य समानता बतलाई है क्योंकि वास्तव में प्रशासन का प्रत्येक पहलु निर्णय निर्माण के इर्द-गिर्द घूमता है।
- हबर्ट साइमन से अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर (Administrative Behaviour) जो वर्ष 1947 में प्रकाशित हुई, इस विषय का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। उन्होने प्रशासनिक व्यवहार के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिए निर्णयन या निर्णय निर्माण (Decision Making) को प्रमुख इकाई है। निर्णय या विनिश्चयन के अध्ययन के द्वारा उन्होने प्रशासन को नवीन तकनीकें, शब्दावली एवं दृष्टिकोण प्रदान किया है।

☞ क्या आप जानते हैं?

- निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का सर्वप्रथम विश्लेषण **चेस्टर बर्नाड** ने किया। किन्तु इस सन्दर्भ में **हरबर्ट साइमन** ने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

★ निर्णय निर्माण की परिभाषाएं:

- **चेस्टर बर्नाड** के अनुसार “निर्णय की प्रक्रिया चयन के क्षेत्र को संकुचित करने की तकनीक है।” दूसरे शब्दों में कहा जाए तो निर्णय मुख्यतः विकल्पों को संकुचित करने की तकनीक है।
- **वैबस्टर शब्दकोष** के अनुसार, ‘निर्णय लेने से आशय अपने मस्तिष्क में सम्मति अथवा कार्यवाही के तरीके निर्धारण से है।’
- **हरबर्ट साइमन** के अनुसार, ‘निर्णय लेना ही प्रशासन है तथा यह उपलब्ध वैकल्पिक संसाधनों के मध्य से अनुकूलतम तार्किक चयन है।’
- **पीटर ड्रकर (मैनेजमेंट गुरु)** के अनुसार, “प्रबंध जो कुछ भी करता है निर्णय के द्वारा करता है।”
- **पॉल एपिलबी** के अनुसार, “नीति निर्धारण ही लोक प्रशासन का सार है।”
- **टैरी** के अनुसार, “प्रबंधकों का जीवन ही निर्णय लेना है।”
- **सेकलर** के अनुसार, निर्णयन को बहुल क्रिया नाम दिया।

निर्णय की विशेषताएं

निर्णय की विशेषताएं

- निर्णय लक्ष्योन्मुखी है
- निर्णय नकारात्मक व सकारात्मक है
- निर्णय समयकालिक है
- निर्णय मानसिक है
- पूर्व निर्णय बाद वाले को प्रभावित करते हैं
- निर्णय तर्कपूर्ण किया है
- निर्णय नियोजन का अंग है

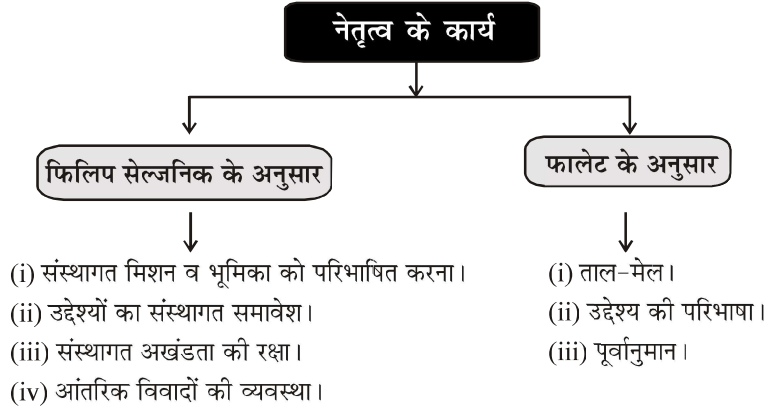
☞ क्या आप जानते हैं?

- निर्णय न करना भी एक निर्णय है और निर्णय स्वयं एक लक्ष्य नहीं है यह अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन है।

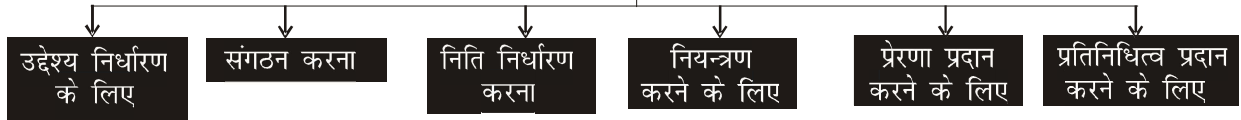
क्या आप जानते हैं?

- शैक्षिक संस्थाओं से संबंधित नेतृत्व जिसमें प्रशासक नेता के रूप में संस्था के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/कुलपति आदि होते हैं, शैक्षिक नेतृत्व कहते हैं।

नेतृत्व के कार्य



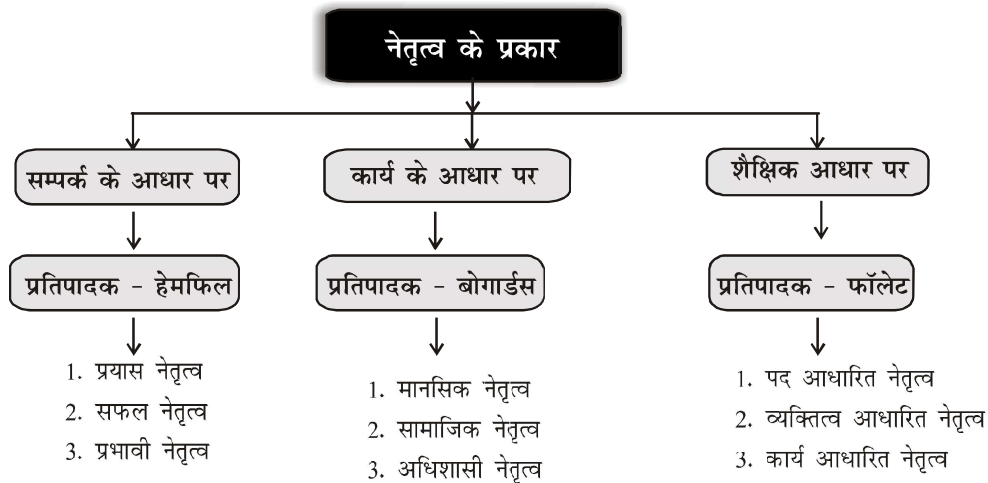
शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता



नेतृत्व की विशेषताएँ

- नेतृत्व में अनुयायियों (अधीनस्थों) का होना आवश्यक है।
- नेता तथा उसके अनुयायियों (अधीनस्थों) के बीच हितों की एकता होनी चाहिए।
- नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है, जो निरन्तर चलती रहती है।
- नेतृत्व में नेता का व्यवहार तथा आचरण आदर्श होना चाहिए क्योंकि नेतृत्व में अनुयायियों के आचरण एवं व्यवहार को प्रभावित किया जाता है।
- नेतृत्वकर्ता तथा अनुयायियों के मध्य क्रियाशील सम्बन्ध होने चाहिए।
- नेतृत्व के लिए परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि परिस्थितियाँ ही नेतृत्व की परीक्षक होती हैं।
- नेतृत्व करने वाला व्यक्ति संगठन में सामान्य उद्देश्यों की तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुयायियों के प्रयासों का निर्देशन व मार्गदर्शन करता है।
- नेतृत्वकर्ता को नेतृत्व से सम्बन्धित आवश्यक योग्यताओं तथा नेतृत्व का आत्मबोध होना आवश्यक है।

नेतृत्व के प्रकार



4

प्रथम व द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

+ प्रशासनिक सुधार का आशय:

- प्रशासनिक सुधार से तात्पर्य प्रशासन में इस प्रकार के सुनियोजित परिवर्तन लाना है जिनसे वह अपनी क्षमताएं बढ़ा सके एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सके। प्रशासनिक विकास की यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सुनियोजित एवं संगठित होने के साथ-साथ निरन्तरता एवं सृजनशीलता की अपेक्षा करती है।
- आधुनिक काल में सभी राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन के परिवेश से गुजर रहे हैं। इस प्रक्रिया में इन राष्ट्रों के सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्य नवीन आवश्यकताओं के अनुसार तीव्र गति से परिवर्तित होते हैं। इन प्रगतिशील लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासन की संरचना, प्रक्रिया एवं दर्शन आदि में अपेक्षित सुधार किया जाना आवश्यक है। प्रशासनिक परिवर्तन या सुधार की यह व्यवस्था आज विकसित एवं विकासशील दोनों ही प्रकार के राष्ट्रों में देखने को मिलती है, किन्तु भारत जैसे परम्परावादी समाज एवं प्रशासनाश्रित व्यवस्था के लिए यह विशेष महत्व रखती है। हमारे संविधान में वर्णित आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता एवं न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोक प्रशासन का अत्यधिक एवं विशिष्ट उत्तरदायित्व है। वस्तुतः भारत में आजकल प्रशासन में सुधार तीन कारणों से आवश्यक हो गया है :
 - (i) **राजनीतिक परिवर्तन** - भारत का प्रशासनिक ढांचा औपनिवेशिक राज के न्यस्त स्वार्थों की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया था।

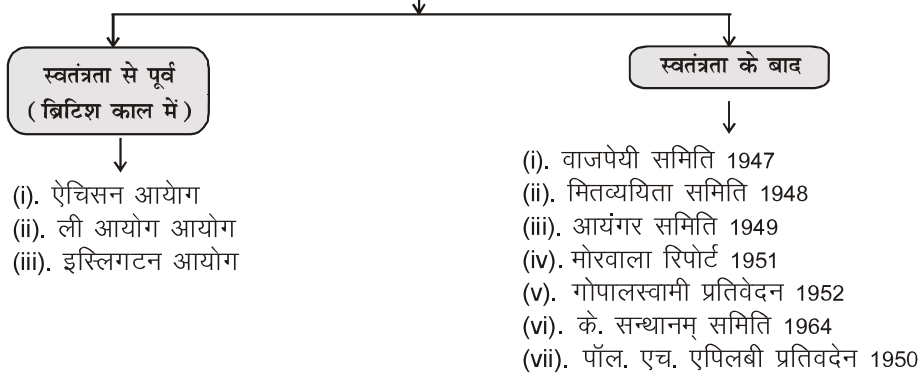
ब्रिटिश युग में सरकारी शासन पद्धति का प्रमुख ध्येय कानून तथा शासन की व्यवस्था बनाए रखना था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद होने वाले राजनीतिक परिवर्तन ने शासन पद्धति में भी परिवर्तन करना आवश्यक बना दिया, क्योंकि नवीन परिस्थितियों में पुरानी पद्धतियों से काम नहीं चल सकता था।

- (ii) **पंचवर्षीय योजनाएं** - स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा भारत के आर्थिक-सामाजिक ढांचे में क्रान्तिकारी मौलिक परिवर्तन करने का निश्चय किया। इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए भारत के प्रशासनिक ढांचे को बदलना और उसको पुनः संगठित करना अतीव आवश्यक हो गया।
- (iii) **भ्रष्टाचार का निवारण**- स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार तथा अन्य बुराइयों में वड़ी वृद्धि हुई है। प्रशासनिक सुधार द्वारा इन्हें रोकने के उपाय खोजना आवश्यक है।

+ भारत में अंग्रेजी शासन काल में प्रशासनिक सुधार

- अंग्रेजी शासन काल में सरकार वैधानिक परिवर्तनों को करने से पहले प्रायः देश की प्रशासनिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए शाही आयोग नियुक्त किया करती थी। ये आयोग अपने क्षेत्र से सम्बद्ध समस्याओं की विस्तृत एवं गहरी जांच तथा छानबीन करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। ये आयोग प्रशासन की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए भारत के विभिन्न प्रान्तों और प्रदेशों का दौरा करते थे। इस युग में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रमुख आयोग थे:

प्रशासनिक आयोग की स्थापना से पूर्व प्रयास



+ ब्रिटिश काल के प्रयास

1. **ऐचिसन आयोग:** ऐचिसन आयोग ने सिविल सर्विस का तीन बड़ी श्रेणियों- शाही सेवाएं, प्रान्तीय सेवाएं तथा अधीनस्थ सेवाएं में बांटने की सिफारिश की।
2. **ली आयोग:** ली आयोग ने उच्च सेवाओं में आवश्यक परिवर्तन के सुझाव दिए। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को चलाने के लिए भारतीय प्रशासन में आवश्यक सुधारों हेतु सुझाव देने के लिए **रिचर्ड टाटनहम** की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी, किन्तु विभाजन की समस्या जटिल हो जाने के कारण इसके प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

5

नागरिकों की शिकायतों का निवारण: लोकपाल, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार

लोकपाल

- स्वीडन में ओम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना 1809 में की गई। ओम्बुड्समैन का शाब्दिक अर्थ है—प्रतिनिधि या वकील। यह शब्द स्वीडिश भाषा के शब्द ऑम्बड से व्युत्पन्न हुआ है। इस अधिकारी का कार्य था कि वह इस बात को देखे कि सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

क्या आप जानते हैं?

- फिनलैंड में इस संस्था की स्थापना = 1919
- डेनमार्क में इस संस्था की स्थापना = 1955
- नार्वे में इस संस्था की स्थापना = 1962
- ब्रिटेन में **पार्लियामेन्टरी कमिश्नर** की स्थापना = 1967 (सर जॉन व्याट को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया।)
- रूस एवं हंगरी में इस संस्था को पब्लिक प्रोक््यूरेटर के नाम से जाना जाता है।

लोकपाल के विकास के चरण

- 1960 में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन द्वारा इस प्रकार की किसी संस्था की स्थापना की आवश्यकता प्रकट की गई। भारत में ओम्बुड्समैन का विचार सर्वप्रथम 1960 के दशक की शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया।
- 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा भी इस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस प्रकार की संस्था गठित की जाने की बात की।
- सर्वप्रथम 1963 में लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान **एल.एम. सिंघवी** ने लोकपाल नामक संस्था की चर्चा की। संसद में सर्वप्रथम लोकपाल शब्द का प्रयोग एल.एम. सिंघवी (जोधपुर के प्रसिद्ध कानूनविद) ने किया (3 अप्रैल, 1963)।
- प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (5 जनवरी, 1966 को श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित) ने सर्वप्रथम अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में लोकपाल एवं लोकायुक्त नामक संस्थाओं की स्थापना की सलाह दी।
- पहला प्रयास** - सर्वप्रथम इन्दिरा सरकार के कार्यकाल में **चौथी लोकसभा में (9 मई, 1968)** शान्ति भूषण द्वारा लोकसभा में लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया। यह बिल लोकसभा में तो पारित हो गया किन्तु राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। इस बिल में प्रधानमंत्री एवं सांसदों को लोकपाल की परिधि से बाहर रखा गया।

- दूसरा प्रयास:** इन्दिरा सरकार ने पाँचवी लोकसभा में (अगस्त, 1971) में इस बिल को पुनः प्रस्तुत किया गया। किन्तु यह बिल भी व्यपगत (Lapse) हो गया।
- तीसरा प्रयास:** जुलाई, 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में तीसरी बार इस बिल को प्रस्तुत किया गया। इस बिल में प्रधानमंत्री को तो लोकपाल की परिधि से बाहर रखा गया किन्तु सांसदों को इसके दायरे में लाया गया।
- चौथा प्रयास:** वर्ष 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा लोकपाल बिल को चौथी बार प्रस्तुत किया गया किन्तु सरकार द्वारा यह बिल वापस ले लिया गया।
- पाँचवा प्रयास:** वर्ष 1989 में वी.पी. सिंह सरकार के कार्यकाल के दौरान पाँचवी बार इस बिल को प्रस्तुत किया गया। सरकार द्वारा प्रस्तुत बिल में प्रधानमंत्री को इसके दायरे में लाया गया। यह पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री को लोकपाल की परिधि में लाया गया।
- छठा प्रयास:** वर्ष 1996 में प्रधानमंत्री देवेगौडा की सरकार द्वारा छठवीं बार इस बिल को प्रस्तुत किया गया। इस बार भी प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया गया। किन्तु 1997 में संसद के भंग होने के बाद यह बिल भी समाप्त हो गया।
- सातवां प्रयास:** वर्ष 1998 में 12वीं लोकसभा में वाजपेयी सरकार द्वारा 7वीं बार।
- आठवां प्रयास:** वर्ष 2001 में आठवीं बार इस बिल को प्रस्तुत किया। इस बिल में प्रधानमंत्री को लोकपाल की परिधि में रखा गया।
- नवां प्रयास:** 4 अगस्त, 2011 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा 9वीं बार यह बिल प्रस्तुत किया गया। 8 अगस्त, 2011 को इस बिल को संसदीय सर्टेडिंग कमेटी को सौंप दिया गया।
- दसवां व ग्याहरवां प्रयास:** 22 दिसम्बर, 2011 को 10वीं बार इस बिल को पुनः लोकसभा में प्रस्तुत किया गया एवं 27 दिसम्बर, 2011 को लोकसभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया। राज्यसभा में इस बिल को 29 दिसम्बर, 2011 को प्रस्तुत किया गया एवं राज्य सभा द्वारा 21 मई, 2012 को यह बिल राज्यसभा की सलैक्ट कमेटी को सौंप दिया गया।
- ★ **लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट—2013**
- 17 दिसम्बर, 2013 को राज्यसभा द्वारा एवं 18 दिसम्बर, 2013 को लोकसभा द्वारा उक्त उक्त बिल को पारित कर दिया गया। 1 जनवरी, 2014 को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा उक्त बिल पर हस्ताक्षर किये गये एवं 16 जनवरी, 2014 से यह एक्ट लागू हो गया। यह एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है अर्थात् यह कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। (किन्तु आज दिनांक तक केन्द्र स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति नहीं की जा सकी है।)